जयपुर • कोटा • बीकानेर • उदयपुर • अजमेर • जालोर • हिण्डौनसिटी • चूरू

राष्ट्रदूत

epaper.rashtradoot.com

जालोर

Rashtradoot

फोनः- 226422, 226423 फैक्सः- 02973-226424 वर्षः 20 संख्याः 71 प्रभात जालोर, बुधवार 18 जून, 2025 पो. रजि. /RJ/SRO/9640/2022-24 पृष्ठ 6 मूल्य 2.50 रु.

कांग्रेस ने सचिन पायलट को ''फील्ड'' किया, जातिगत जनगणना को केवल दिखावा साबित करने के लिए

पायलट ने एआईसीसी में आयोजित प्रैस कॉन्फ्रैंस में कहा कि केवल बिहार चुनाव को ध्यान में रखते हुए भाजपा ने ''कास्ट सैन्सस'' को अपनाने का ''नाटक'' किया है, क्योंकि जात का भारी महत्व रहा है मतदान में

-रेणु मित्तल-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 17 जून। कांग्रेस ने आज ओबीसी समुदाय के अपने प्रमुख नेताओं में से एक सचिन पायलट को आगे कर जातीय जनगणना के मुद्दे पर मोदी सरकार पर जोरदार हमला बोला तथा इससे जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दे उठाये। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार इस विषय पर गंभीर नहीं है और लोगों की आंखों में धूल झोंकने का प्रयास कर रही है।

एआईसीसी मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रैंस को संबोधित करते हुए पायलट ने कहा कि केन्द्र सरकार, जो अब तक जातीय जनगणना को पूरी तरह नकारती रही, जिसमें स्वयं प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने इसे शहरी नक्सल का काम कहा था और राज्य मंत्री ने इसे स्वीकार करने से इनकार किया, वह भी राहुल गांधी और कांग्रेस के भारी दबाव में आकर आखिरकार इसे स्वीकारने को मजबूर हुई।

- पायलट ने अपनी इस सोच के समर्थन में दो तर्क पेश किये। पहला तर्क है, केन्द्रीय सरकार ने देश भर में ''कास्ट सैन्सस'' कराने के लिए केवल 574 करोड़ रूपये का ही प्रावधान किया है, जबकि इस काम को ढंग से कराने के लिए 8 से 10,000 करोड़ रूपये की लागत आने का आंकलन है। इतना कम बजटीय प्रावधान, ''कास्ट सैन्सस'' कराने के बारे में केन्द्र सरकार के गैर गंभीर होने का प्रमाण है।
- पायलट का दूसरा तर्क है, केन्द्रीय सरकार 2027 में यह ''कास्ट सैन्सस'' कराना चाहती है। दो साल का विलंब क्यों? सचिन का कहना है, एक बार चुनाव हो जाए, उसके बाद ''कास्ट सैन्सस'' का मुद्दा आसानी से ठंडे बस्ते में डाल दिया जा सकता है, जैसे, महिला आरक्षण विधेयक ठंडे बस्ते में डाला हुआ है।

पायलट ने बताया कि सरकार द्वारा जारी की गई जनगणना अधिसूचना में जाति जनगणना का कोई उल्लेख नहीं है और इसके लिए बजट में महज 574 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है, जबकि इसकी वास्तविक लागत 8,000 से 10,000 करोड़ रूपए के बीच होगी।

उन्होंने कहा कि कांग्रेस चाहती है कि जातीय जनगणना तेलंगाना मॉडल पर हो, जहाँ विशेषज्ञों से सलाह लेकर ऐसा फॉर्मेट तैयार किया गया, जिसमें शैक्षिणक योग्यता, आर्थिक स्थिति, जीविका का स्वरूप, सरकारी नौकरियों में भागीदारी और अन्य महत्वपूर्ण जानकारी शामिल की गईं।

सचिन पायलट ने आरोप लगाया कि महिला आरक्षण विधेयक की तरह ही सरकार जाति जनगणना के मामले में भी आँख मिचाली खेल रही है और वास्तव में किसी भी वर्ग की वास्तविक स्थिति को समझने में उसकी कोई रुचि नहीं है।

उन्होंने कहा कि सरकार केवल इसलिए यह प्रक्रिया चला रही है, क्योंकि बिहार में चुनाव नज़दीक हैं, जहाँ जाति सबसे बड़ा मुद्दा होता है और वहाँ के लोग अन्य बिन्दु से कहीं ज्यादा जाति के आधार पर ही मतदान करते हैं।

पायलट ने एक और अहम मुद्दा उठाया, जनगणना वर्ष 2027 में क्यों कराई जा रही है, जबकि इसमें अभी दो साल का समय शेष है। इससे स्पष्ट है कि सरकार इस मुद्दे को लगातार टाल रही है और इसमें उसकी कोई रुचि नहीं है। यह सिर्फ कांग्रेस के दबाव का नतीजा है कि सरकार को यह कदम उठाना पड़ा।

'कुछ देर में परीक्षा शुरु हो रही है, मामले की सुनवाई नहीं हो सकती'

जयपुर, 17 जून। राजस्थान हाईकोर्ट ने आरएएस मुख्य परीक्षा 2024 में दखल देने से इनकार कर दिया है। अवकाशकालीन न्यायाधीश मनीष शर्मा की एकलपीठ ने मंगलवार को याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया। अदालत ने कहा कि कुछ देर में परीक्षा शुरु होने वाली है। ऐसे में अब मामले की सुनवाई नहीं की जा सकती हैं।

याचिका में अधिवक्ता तनवीर अहमद ने बताया कि आरपीएससी की ओर से 17 और 18 जुलाई को आरएएस भर्ती-2024 की मुख्य परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है,

- हाई कोर्ट ने आरएएस 2024 की परीक्षा में दखल देने से इंकार किया।

जबकि फिलहाल आरएएस भर्ती-2023 की भर्ती प्रक्रिया ही पूरी नहीं हुई है। इस समय, उस परीक्षा के वर्तमान में साक्षात्कार कर चले हैं। ऐसे में बीते साल की इस परीक्षा की प्रक्रिया पूरी होने तक आरएएस-2024 की मुख्य परीक्षा को स्थगित किया जाए। याचिका में यह भी कहा गया कि प्रदेश के दोनों उपमुख्यमंत्री, एमएलए और एमपी मुख्य परीक्षा को स्थगित करने की सिफारिश कर चुके हैं। उनकी सिफारिशों को देखते हुए परीक्षा स्थगित होने के निर्णय का इंतजार करने के बाद अंतिम समय पर याचिका दायर की गई है। याचिका में यह भी कहा गया कि भारत-

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

ट्रंप जी 7 शिखर वार्ता को बीच में छोड़कर अचानक अमेरिका रवाना हुए

वे ईरान-इज़रायल युद्ध में अमेरिका की भूमिका के बारे में अहम् निर्णय लेने की बात कहकर कैनडा से रवाना हुए

-अंजन रॉय-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

ऑटवा,(कैनडा),17 जून। अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप ने कैनडा की रॉकी पर्वत श्रृंखला के बीच स्थित बैनफ में हो रहे 7 शिखर सम्मेलन को अचानक छोड़ कर स्वदेश लौट गए, ताकि वे मध्य पूर्व में ईरान से जुड़े गंभीर और तात्कालिक हालात से निपट सकें। इससे पहले, इज़राइल ने ईरान के भीतर हमले कर उसके परमाणु हथियारों की क्षमताओं को नष्ट करने की कोशिश की थी।

ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ज़रिए तेहरान के नागरिकों से सुरक्षा की खातिर तुरंत शहर छोड़ने की अपील की है। रिपोर्टों के अनुसार, ईरान के नागरिक भयभीत हैं और राजधानी एवं आसपास के इलाकों से कैस्पियन सागर की ओर पलायन कर रहे हैं। वहीं, पेट्रोल पंपों और जरूरी सामान की दुकानों पर लंबी कतारें देखी जा रही हैं।

- इज़रायल ने पिछली रात ईरान पर पुनः भारी अटैक किया तथा ईरान की न्यूक्लियर सुविधाओं को एकदम नेस्तानाबूद करने के कगार पर है।
- पर, धार्मिक शहर कोम के पर्वतों में जमीन के 250 से 300 फीट नीचे बनी सुरंगों में अभी भी ईरान के कुछ न्यूक्लियर प्रतिष्ठान सुरक्षित हैं।
- इन सुरंगों को नष्ट करने के लिए इज़रायल को अमेरिका द्वारा प्रदत्त ''बंकर बस्टिंग बम'' के इस्तेमाल की अनुमति की आवश्यकता है और ''बंकर बस्टिंग बम'' केवल अमेरिका के बी-52 विमान ही युद्ध स्थल तक ले जा सकते हैं, दागने के लिए।
- अभी तक अमेरिका ने इन बमों और बी-52 विमानों को ईरान के खिलाफ उपयोग में लाने के लिए अपनी इजाज़त नहीं दी थी।

राष्ट्रपति ट्रंप इस समय ईरान संकट से जुड़े कुछ बेहद अहम फैसलों के बीच में हैं। इज़राइल, ईरान के पवित्र शहर क़ोम के पास स्थित पहाड़ियों के अंदर बने सबसे महत्वपूर्ण परमाणु ठिकाने को तबाह करने की योजना पर विचार कर रहा है। सैटेलाइट चित्रों से पता चलता है कि ये ठिकाने लगभग 250 से 300 फीट गहराई में स्थित हैं।

इस संबंध में बंकर-बस्टिंग बमों (भूमिगत ठिकानों को नष्ट करने वाले विशेष बम) के इस्तेमाल पर विचार किया जा रहा है। केवल अमेरिका के

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

इण्डस वॉटर ट्रीटी से प्राप्त सरप्लस पानी को राजस्थान तक लायेगी भारत सरकार

इसके लिए भारत सरकार 113 किलोमीटर लम्बी नहर बनायेगी, यह नहर चिनाब-रावी-ब्यास-सतलज नदियों को जोड़ते हुए जम्मू-कश्मीर का सरप्लस पानी, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान की सूखी धरती तक पहुँचायेगी

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 17 जून। जल कूटनीति और रणनीतिक संसाधन योजना में उठाये गये एक बड़े कदम के तहत, भारत ने सिंधु नदी प्रणाली के अतिरिक्त जल की पाकिस्तान को होने वाली आपूर्ति पूरी तरह से रोकते हुए, देश में ही इसका और उपयोग करने की एक बडी योजना बनाई है।

सरकार जम्मू-कश्मीर से 113 किलोमीटर लंबी नहर बनाकर अतिरिक्त जल को पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के सूखाग्रस्त क्षेत्रों में मोड़ने की योजना बना रही है।

- जैसा कि विदित ही है, वर्तमान में भारत का नहर सिस्टम, सतलज, ब्यास नदी का पानी इंदिरा गांधी नहर के मार्फत राजस्थान के गंगानगर इलाके तक पहुँचाता है।
- नई 113 किलोमीटर लंबी नहर भी इंदिरा गांधी नहर सिस्टम का उपयोग करते हुए अब इण्डस वैली वॉटर सिस्टम का सरप्लस पानी गंगानगर तक पहुँचायेगी।
- भारत सरकार बहुप्रतीक्षित व प्रस्तावित कथुआ हाइड्रो इलैक्ट्रिक प्रोजैक्ट को भी नए सिरे से शुरु करते हुए, कथुआ बाँध के पानी से बिजली ही पैदा करेगी, साथ ही इस बाँध के पानी का उपयोग सिंचाई व पीने के पानी की परियोजनाओं में काम में लेगी।

इसके साथ ही केन्द्र सरकार ने लंबे समय से लंबित उझ बहुउद्देश्यीय परियोजना को जम्मू के कठुआ में पुनर्जीवित करने का निर्णय लिया है, जिसका उद्देश्य जलविद्युत उत्पादन के साथ-साथ, सिंचाई और पेयजल की आपूर्ति बढ़ाना है। प्रस्तावित चिनाब-रावी-ब्यास-सतलज नहर इन नदियों के जल नेटवर्क को एक साथ जोड़ देगी, जिससे पाकिस्तान की ओर बहने वाले जल की मात्रा कम हो जाएगी।

शनिवार को केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने घोषणा की कि ''सिंधु जल को प्रस्तावित नहर के माध्यम से राजस्थान के श्रीगंगानगर तक ले जाया जाएगा, तथा उसे वर्तमान में सतलज और ब्यास से जल ले जाने वाली इंदिरा गांधी नहर से जोड़ा जाएगा।''

मुख्यमंत्री आज सांचौर में

जालोर, 17 जून (कासं)। राज्य के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा 18 जून को जालोर जिले के दौरे पर रहेंगे।

प्राप्त कार्यक्रमानुसार, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा 18 जून को दोपहर 12.25 बजे पुलिस लाइन हैलीपेड राजसमन्द से हेलीकॉप्टर के माध्यम से रवाना होकर दोपहर 1.25 बजे हैलीपेड सीलू, सांचौर पहुंचेंगे। इसके बाद दोपहर 1.30 बजे हैलीपेड से कार द्वारा रवाना होकर दोपहर 1.35 बजे सीलू घाट, सीलू पहुंचेंगे, जहां वे सीलू घाट (नर्मदेश्वर) पर पूजन एवं दर्शन करेंगे। इसके उपरांत वे दोपहर 1.50 बजे वन्दे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के तहत कार्यक्रम व सभा में सम्मिलित होंगे। दोपहर 2.30 बजे सीलू घाट से हैलीपेड के लिए रवाना होंगे। दोपहर 2.35 बजे हैलीपेड से हेलीकॉप्टर द्वारा उत्तरलाई एयरपोर्ट बाड़मेर के लिए प्रस्थान करेंगे।

- वे सीलू घाट (नर्मदेश्वर) का पूजन व दर्शन करेंगे, फिर वंदे गंगा जल सरंक्षण जन अभियान के तहत सभा में शामिल होंगे।

कच्चे तेल के परिवहन के लिए 100 टैंकर बनाएगा भारत

दस अरब डॉलर की लागत की इस परियोजना से भारत कच्चे तेल परिवहन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो जाएगा

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 17 जून। भारत की समुद्री स्वायत्तता को मजबूत करने और घरेलू जहाज़ निर्माण क्षेत्र को प्रोत्साहन देने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए भारत सरकार ने 85,000 करोड़ रु. (लगभग 10 अरब डॉलर) की लागत से देश के अंदर 100 से अधिक कच्चे तेल के टैंकरों के निर्माण को स्वीकृति दी है। 'मेक इन इंडिया' कार्यक्रम के तहत यह महत्त्वाकांक्षी परियोजना न केवल बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देगी, बल्कि कुछ औद्योगिक समूहों के लिए एक बड़ा बदलाव भी साबित हो सकती है।

इस आदेश का बड़ा हिस्सा भारत की प्रमुख सार्वजनिक क्षेत्र की शिपयार्ड कंपनियों, कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (सी.एस.एल.) और मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड (एम.डी.एल.)-के साथ-साथ निजी क्षेत्र की स्वान डिफेंस एंड हैवी इंडस्ट्रीज लिमिटेड को मिलने की संभावना है। जहाँ, सी.एस.एल. और एम.डी.एल. का, जटिल नौसेना व वाणिज्यिक जहाज परियोजनाओं को सफलतापूर्वक पूरा करने का रिकॉर्ड है, वहीं, स्वान डिफेंस (पूर्व में रिलायंस नेवल एंड इंजीनियरिंग) की भागीदारी निजी क्षेत्र की वापसी का संकेत देती है, जिसकी ऐतिहासिक संबद्धता अनिल अंबानी से रही है।

- टैंकरों के निर्माण में सार्वजनिक क्षेत्र की शिपयार्ड कम्पनियों कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड और मझगाँव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड के साथ-साथ निजी क्षेत्र की कम्पनी स्वॉन डिफैंस एण्ड हैवी इंडस्ट्रीज़ की भागीदारी होगी।
- कुछ आलोचकों का कहना है कि यह टैंकर भले ही सरकारी नियंत्रण में बनेंगे, इसका वास्तविक नियंत्रण धीरे-धीरे निजी हाथों में जा सकता है, खासकर रिलायंस और अडानी समूह के।

सार्वजनिक और निजी शिपयार्ड की इस रणनीतिक भागीदारी का उद्देश्य औद्योगिक क्षमता का संतुलित वितरण करना है, जो समुद्री आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के सरकार के व्यापक प्रयासों को दर्शाता है।

इन टैंकरों का स्वामित्व सीधे शिपयार्ड या तेल कंपनियों के पास नहीं होगा, बल्कि स्पेशल पर्पज़ व्हीकल्स (एस.पी.वी.) के माध्यम से होगा। इन एस.पी.वी. में शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (एस.सी.आई.), सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों और वित्तीय संस्थानों की हिस्सेदारी होगी। हालांकि, परियोजना की कुल पूंजी का लगभग 70 प्रतिशत ऋण के माध्यम से जुटाया जाएगा, जिससे निजी वित्त पोषकों को अवसर मिलेगा और संभावित रूप से इन महत्वपूर्ण मैरिटाइम एसैट्स (समुद्री परिसंपत्तियों) पर अप्रत्यक्ष निजी नियंत्रण भी बन सकता है।

हालांकि यह योजना सरकारी नेतृत्व में है, लेकिन इसका वास्तविक लाभ देश के दो सबसे बड़े व्यापारिक समूहों-रिलायंस इंडस्ट्रीज़ और अडानी ग्रुप-को मिल सकता है।

मुकेश अंबानी के नेतृत्व में रिलायंस को अनेक माध्यमों से लाभ होने की संभावना है। स्वान डिफैंस की भागीदारी, इसके पूर्व के संबंधों के माध्यम से 2 जहाज निर्माण अनुबंध मिलने् की संभावना को दर्शाती है। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि, जामनगर स्थित रिलायंस की विशाल रिफाइनिंग गतिविधियाँ, इन नए टैंकरों में से कई को चार्टर करेंगी, जिससे कच्चे तेल के परिवहन पर कंपनी का संचालन नियंत्रण हो सकता है।

दूसरी ओर, गौतम अडानी के नेतृत्व वाले अडानी समूह को, विशेष रूप से अडानी पोर्ट्स (जैसे मुंद्रा पोर्ट)

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

सोनिया गांधी की तबियत में सुधार

नयी दिल्ली, 17 जून। कांग्रेस संसदीय दल की नेता सोनिया गांधी के स्वास्थ्य में सुधार हो रहा है। राष्ट्रीय राजधानी के निजी सर गंगाराम अस्पताल के सूत्रों ने मंगलवार को यहां बताया कि श्रीमती गांधी के पेट के संक्रमण में सुधार हो रहा है और उन्हें स्वास्थ्य लाभ हुआ है।

गांधी को पेट में दर्द की शिकायत के कारण रविवार रात यहां सर गंगाराम अस्पताल में भर्ती कराया गया था। अस्पताल के सूत्रों ने बताया कि 78 वर्षीय श्रीमती गांधी को चिकित्सा निगरानी में रखा गया है।

- सर गंगाराम अस्पताल के सूत्रों ने बताया कि सोनिया गांधी के पेट का संक्रमण ठीक हो रहा है।

गांधी की पिछले सप्ताह भी अस्पताल में स्वास्थ्य जांच की गयी थी।

शुरु से लग रहा था, पता नहीं क्या गुल खिलायेंगे ट्रंप कैनडा में आयोजित जी7 सम्मेलन में

इससे पहले जब कैनडा में ही जी7 की बैठक हुई थी, ट्रंप ने मीटिंग के अन्त में तैयार ''जॉइन्ट स्टेटमैंट'' पर हस्ताक्षर करने से इन्कार कर दिया था तथा अपुष्ट समाचार था, उस ''जॉइन्ट स्टेटमैंट'' को फाड़ कर फेंक दिया था

-अजंय रॉय-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

ऑटवा,(कैनडा), 17 जून। दुनिया के सबसे विशिष्ट और प्रभावशाली क्लब कहे जाने वाले जी7 समूह की बैठक आज से कैनडा के खूबसूरत रॉकी पर्वतीय क्षेत्र में शुरू हो रही है। हालांकि इस बार सम्मेलन से उम्मीदें अपेक्षाकृत कम रखी गई हैं। कहा जा रहा है कि मेज़बान कैनडा ने, अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप के अनिश्चित और अप्रत्याशित व्यवहार को देखते हुए, बैठक के अंत में किसी साझा घोषणा पत्र की उम्मीद को त्याग दिया है। भारतीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को जी7 बैठक में आमंत्रित किया गया है, हालांकि भारत इस समूह का सदस्य नहीं है। शुरुआत में भारत की भागीदारी को लेकर कुछ अनिश्चितता थी, लेकिन कई जी7 सदस्य देशों के आग्रह पर मोदी को आमंत्रण भेजा गया, क्योंकि इस बार का एजेंडा वैश्विक आर्थिक मुद्दों पर केन्द्रित है

भारत और कैनडा के संबंध पूर्व प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के कार्यकाल में खालिस्तानी मुद्दे को लेकर तनावपूर्ण हो गए थे। लेकिन अब नव-निर्वाचित प्रधानमंत्री मार्क कार्नी, जो बैंक ऑफ कैनडा और बैंक ऑफ इंग्लैंड के गवर्नर भी रह चुके हैं, ने व्यक्तिगत रूप से मोदी को फोन कर इस सम्मेलन में आमंत्रित किया।

- तभी से ट्रंप के बारे में यह आम धारणा बनी हुई है कि वे जिस भी कमरे में हों, वहाँ सबसे ''डॉमिनैंट व्यक्ति'' (प्रभावशाली व्यक्ति) होना चाहते हैं तथा दूसरों को उनकी बात स्वीकार कराना ही उनका बड़ा ध्येय होता है।
- पर, कैनडा में आयोजित वर्तमान जी7 सम्मेलन में फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रॉं जैसे नेता भी हैं, जो अमेरिका में वाइट हाउस में ट्रंप के दफ्तर में ट्रंप को आईना दिखाकर बाहर आये थे। इन हालात में शिखर सम्मेलन में काफी आतिशबाजी होने की आशंका थी।

जी7 के शिखर सम्मेलन में आर्थिक मुद्दों पर केन्द्रित लघु मीटिंग्स होंगी, जिनमें वैश्विक व्यापार, आर्टिफिशल इंटेलिजेंस, टैरिफ और इमिग्रेशन जैसे मुद्दों पर चर्चा की जाएगी।

भारत के लिए यह सम्मेलन महत्वपूर्ण हो सकता है, विशेषकर व्यापार और शुल्क के मुद्दों पर प्रगति हासिल करने के लिए। ट्रंप द्वारा भारत पर पारस्परिक शुल्क लागू किए जाने के बाद मोदी और ट्रंप यहाँ व्यक्तिगत रूप से पहली बार मिलेंगे। ट्रंप कई बार दावा कर चुके हैं कि भारत के साथ व्यापार समझौता जल्द ही हो सकता है और इस मंच पर किसी ठोस प्रगति की घोषणा उनके लिए चुनावी दृष्टि से भी फायदेमंद हो सकती है।

ट्रेड अमेरिकी राष्ट्रपति का ट्रंप कार्ड है। वे व्यापार गतिरोध को तोड़ने के अपने सौदों पर अड़ जाते हैं। वे अक्सर समझौतों की भी जल्दबाज़ी में, समय से पहले ही, घोषणा कर देते हैं।

ट्रंप की नाटकीय शैली से अलग इस बार का जी7 सम्मेलन ऐसे समय में हो रहा है, जब मध्य पूर्व में बढ़ते युद्ध और अस्थिरता से दुनिया को गंभीर खतरे हैं। इज़राइल और ईरान के बीच संघर्ष के अचानक तेज़ होने से वैश्विक

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

नाबालिग का अपहरण, दुष्कर्म करने वाले को 10 साल की सजा

जयपुर, 17 जून। जिले की पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत ने करीब 14 साल की नाबालिग विवाहिता का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त नितिन कुमार को दस साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही, अदालत ने 24 वर्षीय इस अभियुक्त पर एक लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। पीठासीन अधिकारी केसी अटवासिया ने अपने आदेश में कहा कि वर्तमान में नाबालिगों के साथ लैंगिक अपराध बढते जा रहे हैं। ऐसे में अदालत का कर्तव्य है कि अभियुक्त को उसके किए गए अपराध के लिए दंडित करे।

- पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत ने सजा के साथ एक लाख रूपये जुर्माना लगाया।

अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

CMYK